

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 5338/2025

लालचन्दयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 31 अन्यप्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार तिवारी, गोपाल दास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पटल पर उपलब्ध मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: "(i) उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 1094/24-25, शोभनाथ बनाम लालचन्द एवं अन्य (संलग्नक संख्या 1) में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.06.2025 को रद्द किया जाए। (ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा अपील संख्या 1094/24-25, शोभनाथ बनाम लालचन्द एवं अन्य, यू.पी. सी.एच. अधिनियम की धारा 11(1) के तहत दायर रिकॉल आवेदन दिनांक 18.09.2025 को यथाशीघ्र, अधिमानतः एक महीने के भीतर तय करें।"
3. काफी देर तक विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने केवल राहत संख्या 2 पर बल दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को उपर्युक्त रिकॉल आवेदन को निर्धारित अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर तय करें।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

विनय